(c) if so, the details thereof; and

(d) the amount spent on food subsidy during 1994-95 and the amount of additional subsidy required for the same during 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (d) As per present policy of Central Government, there is only one type of Public Distribution System (PDS) in the country. However, in order to improve the functioning of the PDS in backward regions of the country, about 2446 blocks have been covered under the Revamped Public Distribution System (RPDS). In the blocks covered under RPDS, States have been advised to ensure availability of 20 kgs of food grains per household per month. Central Government issues foodgrains meant for distribution in RPDS areas to States/UTs at specially subsidised Central Issue Prices (CIPs) which are Rs. 50/- per quintal lower than the CIPs for the PDS. These specially subsidised CIPs are not applicable to urban agglomerations within the RPDS blocks in non-tribal majority States.

Central Government has no proposal to formulate any scheme for providing ration to urban poor at cheaper rates than arc applicable to rural poor.

The total amount of food subsidy (including sugar) during 1994-95 was Rs. 5100 crores as per Revised Estimates. A budgetary provision of Rs. 5250 crores has been made for food subsidy for the year 1995-96.

**Hospitals for Workers in Industrial Area**

2181. SHRI MOHAN BABU: Will the Minsiter of LABOUR be Pleased to state:

(a) whether Government will consider a scheme to direct the Provident Fund Commissioner to build and run one high quality hospital for workers in every industrial area;

(b) whether any such plan has been mooted; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**इलाहाबाद जल संस्थान के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन**

2182. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से उस योजना के कार्यान्वयन की कोई जांच कराई हैं, जिसके लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक सांसद की संस्तुति पर इलाहाबाद के लिजा कलेक्टर द्वारा इलाहाबाद जल संस्थान को धनराशि प्रदान की गई थी;

(ख) क्या मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इस संबंध में जाचं करने के लिए इलाहाबाद गए थे और क्या उन्होने इसकी जांच की थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध मे क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुशांसित निर्माण कार्यो के संबंध में जल संस्थान , इलाहाबाद द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के उपयोग से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अपर सचिव ने इलाहाबाद का दौरा किया।

(ग) अपर सचिव द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि माननीय सांसद श्री सत्य प्रकाश मालवीय, डा. एम.एम. जोशी एव. श्रीमती सरोज दुबे द्वारा

अनुशंसित निर्माण कार्यो को पूरा करने के लिए आबंटित निधियों का जल संस्थान ने विपथन/दुरूपयोग किया हैं।

अपर सचिव द्वारा की गई जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित आग्रह करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई:

(1) इस मामले में एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए तथा दुरूपयोग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई आरंभ की जानी चाहिए।

(2) जल संस्थान को दुरूपयोग की गई धनराशि को तुरंत प्रभाव से वापस करने, अनुदान सहायता खाते में अधिशेष धनराशि को नहीं निकालने तथा खाते को प्रतिबंधित करने के लिए अनुदेश दिए जाने चाहिए।

(3) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जल संस्थान को दी गई निधियों की महालेखाकार के द्वारा तत्काल लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।

(4) संबंधित जिला कलेक्टर को जल संस्थान द्वारा नहीं शुरू किए गए निर्माण कार्यो को वापस लेने तथा भविष्य मे यह सुनिश्चित करने कि कार्यान्वयन अभिकरण को दिए गये निर्माण कार्यो की वास्तविक प्रगति की समीक्षा किए बिना धनराशि को जारी न किया जाए, के सुझाव दिये जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने यह सूचित किया हैं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं।

निधियों के विपथन/दुरूपयोग के लिए जबावदेह वित्तीय अधिकारी को निलंबित किया जा चुका हैं तथा महाप्रबंधक जो उस समय जल संस्थान के प्रमुख थे, को स्थानांतरित कर दिया गया हैं।

**Medical Facilities to Bccdi Workers**

2183. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether medical fecilities are being provided to all beedi workers;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the percentage of those bccdi workers to whom the medical facilities are being provided by Government, State wise?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a)and (b) A'chain of 154 dispensaries and 3 hospitals have been set up under the Bccdi Workers Welfare Fund all over the country exclusively for beedi workers to supplement the medical facilities available at the District Hospital/Rural Hospitals/ Public Health Ccntres/Sub-Centres etc. run by the State Governments

(c) A Statement is annexed.

**Statement**

| State | % of beedi workers covered as per minimum norms. | % of beedi workers actually covered as ported by Welfare Commissioners. |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 7.3% | 20.83% |
| Tamilnadu | 7.3% | 20.83% |
| Orissa | 33.7% | Under verification. |
| Madhya Pradesh | 16.2% | 60% |
| Rajasthan | 30% | 76.5% |
| Gujarat | 50% | 71.0% |
| West Bengal | 11.3% | 30% |
| Assam | 65% | 78% |
| Tripura | 100% | 92% |
| Maharashtra | 27.8% | 44% |
| Karnataka | 21.7% | 50% |
| Kerala | 29.7% | 50% |
| Bihar | 17% | 47% |
| Uttar Pradesh | 12.2% | 33% |